



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—पाठ 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[No. 229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 1990/भाद्र 23, 1912

[No. 229]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 1990/BHADRA 23, 1912

हम भाग में भिन्न पाठ संख्या वाली आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय
नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1990
संकल्प

सं. 50/4/18/88-टी०ग्स०.—सरकार ने गांधीय सुरक्षा के मध्ये एक दृष्टिकोण पर समन्वित एवं व्यापक ढंग से विचार करने के लिए एक गांधीय सुरक्षा परिषद् गठित करने की अपनी छँड़ा की घोषणा की थी। यह परिषद् विदेशी, प्रार्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य स्थितियों और हमारी चर्चा वित्तान्द्रों एवं उद्योगों से उनके भवित्वों को ध्यान में रखने हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर मध्यूर्ण धृष्टिकोण घोषणेगी।

2. ऐसी व्यापक भौतिकिक सामरिक महत्व का वातावरण तथा देश की आंतरिक परिस्थिति दोनों ही तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए मध्यूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता का आज विशेष महत्व है। अत्यर्थीय वातावरण में शाक्तीय परिवर्तन हुए हैं जिसमें संसार के विविध श्रेणियों में अनिवार्य रूप से मानित के नये संतुलन की स्थापना को बहावा दिखेगा। प्रार्थिक सोच विचार द्वारा ज्यादातर अत्यर्थीय राजनीतिक गतिविधियां निवारित की जा रही हैं। ऐसे विषयों में सामाजिक तथा प्रशासनिक ढंग पर व्यावर है। देश के कुछ भागों में ये प्रवृत्तियां बहुत ताकतों द्वारा संयोजित की जाती

हैं जो उम्रवारी तथा आसंकवादी भंगठों को उनकी गैर-कानूनी एवं व्यवसायक गतिविधियों में मदद देती हैं एवं बढ़ावा देती हैं। अगर इन प्रवृत्तियों को बीर रोक-टोक के जारी रहने दिया जाता है, तो ये राष्ट्र की एकता एवं अस्थिरता को भर्ति पहुंचा सकती है।

3. अतः सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

प्रधानमंत्री —प्रध्यक्ष

रक्षा मंत्री —प्रदस्त्य

वित्त मंत्री —सदस्य

गृह मंत्री —सदस्य

विदेश मंत्री —सदस्य

यह परिषद् आवश्यकतानुसार अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा किसी राज्य के मुख्य मंत्री को परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुरोध कर सकती है। यह परिषद् आवश्यकतानुसार सुविक्षों और विशेषज्ञों को भी इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का मुख्य प्रयास होगा राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही व्यापक स्थिति तथा हमारा आंतरिक स्थिति के बीच मध्यविद्यों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण के प्रति

सम्पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना, क्योंकि इसका गान्धीय सुरक्षा पर अपग पड़ता है। इससे उन रणनीतियों की पहचान होगी जो रक्षा, आतंकिक सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में हमारे प्रयासों के प्रचले परिणाम लिखते की आशा बढ़ती है। यह परिषद् इस बात का मन्त्रिभव करेगी कि आतंकिक तथा भौगोलिक सामरिक महत्व के बातावरण का मध्यकालीन तथा वीर्धकालीन मूल्यांकन हो, जिससे कि संबंधित मामलों में अवश्यकी नीति बनाने में परिषद् का काम करे। परिषद् के विचार के लिए औ विषय प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे माटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल करेंगे :

- (क) राज्य अन्तर्गत की स्थिति ।
- (ख) सामरिक सदृश्व की रक्षा संबंधी नीतियाँ ।
- (ग) अन्य सुरक्षा संबंधी अन्तर्गत, विशेष रूप से ऐसे अन्तर्गत जिनका संबंध परमाणु ऊर्जा, अन्तर्रक्षा तथा उच्च टेक्नोलॉजी गे हैं।
- (घ) आन्तरिक सुरक्षा जिसमें प्रतिविहीन, प्रतिक्रियात्मक और प्रभावी सुरक्षा जैसे पक्ष शामिल हैं।
- (इ) देश के भीतर गैंग उत्पादी का संभावना होना, विशेष रूप से जिसका सामाजिक, सांप्रदायिक अधिकार प्रदेशिक आवाय हो।
- (ज) भारत की आधिक तथा विदेशी नीतियों पर विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो गई प्रवृत्तियों की सुरक्षा संबंधी उल्लंघन ।
- (क्ष) उर्जा, खाद्य तथा विद्युत जैसे घोटों में बाह्य आधिक अन्तर्गत ।
- (क्ज) नक्सी तथा हथियारों, ड्रोगों तथा नार्कोटिक के प्रबंध व्यापार जैसे मीमांपार अपराधों से उत्पन्न अन्तर्गत ।
- (क्झ) सामरिक महत्व के तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर गान्धीय महसूति तैयार करना ।

5. गान्धीय सुरक्षा परिषद् ने स्टैटिजिक कोर युद्धांग व्यवस्था प्रशासन की जापी जिसमें सचिव, मन्त्रिमंडल अध्यक्ष और तीनों सेवाओं के प्रतिनिधि तथा संबंधित मंत्रालय होंगे। स्टैटिजिक कोर पूर्ण गान्धीय सुरक्षा परिषद् को मंत्रालयों या अन्य सरकारी एजेंसियों या विशेष टार्फ फॉर्मेस द्वारा जैसे कि पैरा 6 में दर्शाया गया है प्रमुख किए गए कागजाओं और रिपोर्टों के समृच्छित अध्ययन का निरोक्षण करेगा।

6. गान्धीय सुरक्षा परिषद् का अपना एक अलग सचिवालय होगा जिसका प्रमुख सचिव द्वारा और वह अधिकार भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा। यह सचिवालय स्टैटिजिक कोर प्रप की भी सेवाएं प्रशासन करेगा।

7. गान्धीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों के गठन अध्ययन हेतु, परिषद् के अध्यक्ष जितनी चाहें उन्होंने टार्स्क फोर्मेस स्थापित कर सकते हैं। प्रथमेक टार्स्क फोर्मेस द्वारा की सुरक्षा से संबंधित होगी और उसके सदस्य सरकारी सुरक्षा मामलों में कार्यगत संवालयों और एजेंसियों से ही लिए जाएंगे। प्रथमेक टार्स्क फोर्मेस का प्रमुख उस टार्स्क फोर्मेस को संपर्क गण का अन्याय जान और अनुभव रखता होगा। यद्यपि टार्स्क फोर्मेस प्रशासनिक तौर पर गान्धीय सुरक्षा परिषद् के सचिवालय जे जड़ रहेगा, किन्तु सरकारी या आहरी एजेंसियों से विशेषज्ञ सहायता के लिए अनुरोध कर सकता है।

8. गान्धीय सुरक्षा परिषद्, गान्धीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर वेण के भीतर अधिक से अधिक सभावित संवेदनस्थिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महसूर्पूर्ण गान्धीय सुरक्षा भव्यस्थायों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करेंगी। इसके लिए एक गान्धीय सुरक्षा सलाहकार थोर्ड का गठन किया जाएगा जिसके मद्दत्यों को मूल्य-मतियों, भवित्व सदस्यों, विद्यार्थी, वैज्ञानिकों प्रशासन सेवा का अनुभव अनुभव वाले व्यावर्ता, सशस्त्र बलों, प्रेस और समाचार माध्यमों

शामिल किए जाएंगे। थोर्ड की एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होंगी और यह अपनी कार्यवाहियों का रिपोर्ट रखेगा।

बोर्ड, गान्धीय सुरक्षा के मामलों पर विचारी एवं विकल्पों का एक आधिक कानून प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्थल से एक रक्तनालंब में वार्षिक करेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् पर विचार के लिए उन्नत किए जाने वाले कागजाओं एवं उनके अध्यवधन कार्य में महत्वपूर्ण होने का लाभ करेगा। थोर्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के मनिवाल वा सेवाएं प्राप्त होंगी।

विनोद चन्द्र पाण्डे, भविमठन नाम

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 24th August, 1990

RESOLUTION

No. 50/4/18/88-TS.—The Government had announced their intention to set up a National Security Council to consider all aspects of national security in a coordinated and comprehensive manner. The Council will take a holistic view of national security issues in the light of the external, economic, political and military situations and their linkages with our domestic concerns and objectives.

2. The need for a holistic approach is especially important today as both the external geo-strategic environment and the internal situation in the country are changing rapidly. The international environment has undergone dramatic changes which will inevitably lead to the establishment of new equilibria of power in different regions of the globe. Economic considerations are increasingly determining international political dynamics. The domestic situation is also changing and in many regions, the social fabric and the administrative structure is under strain. In some parts of the country these strains are compounded by external forces aiding and abetting militant and terrorist groups in their unlawful and subversive activities. These trends if allowed to go unchecked, could undermine the nation's integrity and unity.

3. Government have, therefore, decided to set up a National Security Council comprising the following

Prime Minister : Chairman

Minister of Defence : Member

Minister of Finance : Member

Minister of Home Affairs : Member

Minister of External Affairs : Member

The Council may, as necessary, request other Union Ministers and any Chief Minister of a State to attend meetings of the Council. The Council may also invite experts and specialists to attend its meetings as necessary.

4. The main endeavour of the National Security Council will be to evolve an integrated approach to policy making as it affects national security, taking account of the linkages between the evolving external situation in the political, Military and economic fields and our domestic situation. This should lead to the identification of strategies which optimise our efforts in defence, internal security and foreign affairs. The council will ensure that medium-term and long-term assessments are made of the internal and geo-strategic environment to serve as a perspective for shaping Government policy in related matters. The subjects submitted for the consideration of the Council will broadly cover the following :

(a) external threat scenario;

(b) strategic defence policies;

(c) other security threats specially those involving atomic energy, space and high technology;

- (d) internal security covering aspects such as counter-insurgency, counter-terrorism and counter-intelligence;
- (e) patterns of alienation likely to emerge within the country, especially those with a social, communal or regional dimension;
- (f) security implications of evolving trends in the world economy on India's economic and foreign policies;
- (g) external economic threats in areas such as energy, commerce, food and finance;
- (h) threats posed by trans-border crimes such as smuggling and traffic in arms, drugs and narcotics;
- (i) evolving a national consensus on strategic and security issues.

5. The National Security Council shall be assisted by a Strategic Core Group comprising the Cabinet Secretary as Chairman and representatives of the three Services and the Ministries concerned. The Strategic Core Group will supervise the submission of appropriate studies, papers and reports to the National Security Council from the Ministries or other agencies of the Government, or from Special Task Forces as indicated in para 7.

6. The National Security Council will have a separate Secretariat which will be headed by a Secretary who will be an officer in the rank of Secretary to the Government of India. This Secretariat will also service the Strategic Core Group.

7. For in-depth study of different aspects concerning national security, Task Forces may be established as may be decided by the Chairman of the Council. Each Task Force will be concerned with specific areas of security and its membership will be drawn from the Ministries and agencies dealing with the security issues within the Government. Each Task Force will be headed by an experienced person well-versed in matters assigned to that Task Force. While the Task Forces will be administratively attached to the Secretariat of the National Security Council, they may request for expert assistance from agencies within or outside the Government.

8. The National Security Council will also oversee efforts to increase public awareness on important national security problems with a view to promoting the widest possible consensus within the country on issues affecting the nation's security. Towards this end, a National Security Advisory Board will be constituted comprising members drawn from among Chief Ministers, Members of Parliament, academics, scientists and persons having rich experience of service in the administration, armed forces, press and the media. The Board will meet at least twice a year and keep a record of its proceedings. The Board will essentially serve as a mechanism for obtaining a broad range of informed views and options on national security issues. This will form an important input into studies and papers submitted for the consideration of the National Security Council. The Board will be serviced by the Secretariat of the National Security Council.

V. C. SHANDE, Cabinet Secy

